एक्सक्लूसिव इंटरव्यू

स्किल इंडिया के लिए इंडस्ट्री से जुड़ेगा करिकुलम

स्किल इंडिया के तहत सरकार तकनीकी संस्थानों के साथ-साथ स्कूलों-कॉलेजों में भी स्किल ट्रेनिंग उपलब्ध कराने की दिशा में प्रयास कर रही है। इस बारे में केंद्रीय स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप राज्य मंत्री राजीव प्रताप रूडी से अरुण श्रीवास्तव ने विस्तार से बात की। इस बातचीत के मुख्य अंश :

▸▸ इंडस्ट्री और एक्सपर्ट्स वर्षों से कह रहे हैं, सरकार भी मान रही है कि उद्योगों को साधारण डिग्रीधारियों की जरूरत नहीं है। उन्हें अब प्रशिक्षित युवा चाहिए। क्या स्किल इंडिया कार्यक्रम को कॉलेजों से सीधे जोड़ने की जरूरत नहीं है?

देश में जो इंजीनियरिंग कॉलेज बंद हो गए हैं या बंद होने के कगार पर हैं, उनके पास जो इक्विपमेंट्स हैं, कैंटीन है, लैब है, फैकल्टी है, ग्राउंड्स हैं, ऐसी संस्थाएं जो डिस्ट्रेस में हैं, वे खुद को कौशल विकास केंद्र के रूप में, मल्टी स्किल सेंटर के रूप में डेवलप करें। हम उनको खड़े होने के लिए आर्थिक मदद करेंगे और ट्रेनिंग पर होने वाले खर्च में भी सहायता करेंगे।

▸▸ कॉलेजों के सिलेबस को इंडस्ट्री की रिक्वॉयरमेंट से जोड़ने के लिए किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं?

जो वर्तमान शिक्षण संस्थान हैं और उनका एलाइनमेंट इंडस्ट्री से नहीं है, यह सबसे बड़ी चुनौती है। इसके लिए हमारा मंत्रालय काम कर रहा है। नेशनल स्किल सर्टिफिकेशन बोर्ड का निर्माण हो रहा है। इसके तहत एनसीटीवी (आइटीआइ) और एनएसडीसी को एक करके हम एक कॉमन करिकुलम-सिलेबस बनाकर उसे सर्टिफाई करने का प्रयास कर रहे हैं।

▸▸ क्या स्किल ट्रेनिंग देते समय यह देखा जा रहा है कि किसे, किस तरह के प्रशिक्षण की जरूरत है? क्या करिकुलम को बनाते समय इंडस्ट्री से राय-मशविरा नहीं किया जाना चाहिए?

इस पर काम शुरू हो चुका है। आज जो एनएसडीसी के तहत सेक्टर स्किल काउंसिल बनाए गए हैं, वे सरकारी काउंसिल नहीं हैं। ये इंडस्ट्री बॉडी द्वारा बनाए गए हैं। यही तय करेंगे कि हमारे उद्योगों में किस प्रकार के रोजगार हैं, किस प्रकार के कौशल प्राप्त नौजवानों की जरूरत है और किस प्रकार का प्रशिक्षण देने से इंडस्ट्री की डिमांड पूरी की जा सकती है। सेक्टर स्किल काउंसिल का मुख्य काम यह है कि जो नौकरियां मार्केट में हैं, उनके सेक्टर में हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन में, लाइफ साइंसेज में, हैवी इक्विपमेंट में, ऑयल सेक्टर में, ऑटोमोबाइल्स में, इन सब में वह देखे कि कहां-कहां नौकरी है, उसके लिए किस तरह की ट्रेनिंग के लिए हमें क्या चाहिए, किस तरह का सिलेबस चाहिए? उसकी तैयारी करके वह हमें देगी।

▸▸ क्या इसके लिए अन्य मंत्रालयों के साथ मिलकर काम करने की जरूरत नहीं है?

बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। भारत सरकार के करीब 24 मंत्रालय संबद्ध योजनाएं चला रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब से कौशल विकास मंत्रालय का गठन हुआ, सबको एक जगह लाइए। इसी का परिणाम है कि आइटीआइ जो पहले मिनिस्ट्री ऑफ लेबर में था, वहां से उठाकर हम इसे अब स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के तहत लाएं हैं। धीरे-धीरे बाकी योजनाएं भी जुड़ेंगी।

▸▸ नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के तहत स्थापित किए जा रहे पार्टनर्स ट्रेनिंग सेंटर्स को लेकर कुछ संशय सरकारी धन के दुरुपयोग का है। ऐसे में ट्रेनिंग की निगरानी के लिए क्या कोई कदम उठाया गया है?

अब ऐसी व्यवस्था पर रोक लग गई है। अब यह स्टूडेंट बेस्ड न होकर ग्रांट बेस्ड होगा, ताकि बिचौलियों पर रोक लगाई जा सके।

▸▸ क्या इस दिशा में कोई कदम उठाया जा रहा है या सोचा जा रहा है कि स्कूली स्तर से ही बच्चों को स्किल ट्रेनिंग दी जा सके?

वर्षों से हमने शिक्षा की तरफ बहुत ध्यान दिया है। शिक्षा में ही निहित है स्किल। जो कि हुआ नहीं। आज तकरीबन साठ हजार प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में से बमुश्किल ढाई हजार विद्यालयों में ही स्किल की पढ़ाई हो रही है। नई शिक्षा नीति में अब हम स्कूली शिक्षा से स्किल को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं।

▸▸ क्या विभिन्न बोर्डों, विश्वविद्यालयों के वर्षों पुराने सिलेबस को बदलने या उन्हें एकीकृत करने के लिए कोई कदम उठाया जा रहा है, ताकि स्टूडेंट्स को अपडेटेड एजुकेशन मिल सके?

अब सभी सिलेबस/करिकुलम को हम रिवाइज कर रहे हैं। नवगठित स्किल सर्टिफिकेशन बोर्ड इस काम को नये सिरे से करेगा। हम एनसीयूएफ एक्ट भी लाने की बात भी कर रहे हैं।

▸▸ स्किल इंडिया, स्टार्ट-अप इंडिया, मेक इन इंडिया, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जैसी तमाम लुभावनी योजनाएं आरंभ की गई हैं। क्या इन पर अमल भी उतनी ही गंभीरता के साथ हो रहा है?

योजनाओं के कार्यान्वयन की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। क्योंकि यह पहली बार इतने बड़े पैमाने पर हो रहा है, तो थोड़ा वक्त लग रहा है। इसकी रूपरेखा मजबूती से बनाई गई है। जिस क्षेत्र में काम चल रहा है, वहां के एमपी, एमएलए बता रहे हैं कि यह बहुत बड़ी योजना है।